

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा: एक समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. ममता जोशी (प्रधानाचार्या)

बी.एस.एम. वूमैन बी.एड. कॉलेज, रुड़की

Article Received: 18 July 2026, Article Revised: 13 August 2026, Published on: 02 September 2026

*Corresponding Author: डॉ. ममता जोशी

बी.एस.एम. वूमैन बी.एड. कॉलेज, रुड़की

Doi: <https://doi-doi.org/101555/ijarp.8550>

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक संरचनात्मक एवं वैचारिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा को विशेष स्थान दिया गया है। परंपरागत शिक्षा व्यवस्था में कला, विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल आधारित विषयों के बीच विद्यमान कठोर सीमाएँ विद्यार्थियों की विषय-चयन स्वतंत्रता तथा समग्र बौद्धिक विकास को सीमित करती रही हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सीमाओं को समाप्त करते हुए ऐसी शिक्षा व्यवस्था की परिकल्पना करती है जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि, योग्यता एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न विषय क्षेत्रों का अध्ययन कर सकें। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा, विशेषताओं, आवश्यकता, प्रमुख प्रावधानों, संभावित लाभों तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन वर्णनात्मक एवं समीक्षात्मक प्रकृति का है तथा इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश, Curriculum and Credit Framework, Academic Bank of Credits, National Credit Framework तथा 2020-2026 के संबंधित शोध अध्ययनों और प्रामाणिक द्वितीयक स्रोतों का अध्ययन किया गया है। समीक्षा से स्पष्ट होता है कि बहुविषयक शिक्षा विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या-समाधान क्षमता, नवाचार, रोजगारपरक कौशल तथा सामाजिक और नैतिक संवेदनशीलता के विकास की व्यापक संभावनाएँ प्रस्तुत करती है। हालांकि प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, संस्थागत अवसंरचना, पाठ्यक्रम समन्वय, संसाधनों की असमानता तथा प्रशासनिक तैयारी इसके प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन निष्कर्ष देता है कि पर्याप्त संस्थागत स्वायत्तता, शिक्षक प्रशिक्षण, संसाधन उपलब्धता तथा छात्र-केंद्रित

पाठ्यक्रम व्यवस्था के माध्यम से बहुविषयक शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी और भविष्यन्मुख बना सकती है।

मुख्य शब्द: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, बहुविषयक शिक्षा, समग्र शिक्षा, उच्च शिक्षा, पाठ्यक्रम लचीलापन, Academic Bank of Credits, कौशल विकास।

1. प्रस्तावना

शिक्षा का उद्देश्य केवल किसी एक विषय में तथ्यात्मक ज्ञान प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक एवं व्यावसायिक विकास को सुनिश्चित करना है। वर्तमान वैश्विक समाज में पर्यावरण परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक असमानता, सतत विकास तथा सामाजिक परिवर्तन जैसी समस्याएँ इतनी जटिल हो चुकी हैं कि उनका समाधान किसी एक विषय के ज्ञान से संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों को एक-दूसरे से जोड़ने वाली शिक्षा की आवश्यकता तेजी से बढ़ी है।

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इसी आवश्यकता को स्वीकार करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक तथा विद्यार्थी-केंद्रित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। नीति स्पष्ट रूप से कला एवं विज्ञान, पाठ्यक्रम एवं सह-पाठ्यक्रम, शैक्षणिक एवं व्यावसायिक तथा सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान के बीच कठोर विभाजन को कम करने पर बल देती है। उच्च शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों के रचनात्मक संयोजन चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करने की परिकल्पना करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लिखित बहुविषयक शिक्षा भारतीय परंपरा से पूर्णतः अलग अवधारणा नहीं है। प्राचीन भारत के तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे शिक्षण केंद्रों में विभिन्न ज्ञान-विषयों के अध्ययन की परंपरा विद्यमान थी। NEP 2020 इसी समग्र ज्ञान परंपरा को आधुनिक आवश्यकताओं, विज्ञान, तकनीकी विकास, कौशल, शोध तथा रोजगारपरकता से जोड़ने का प्रयास करती है।

2. बहुविषयक शिक्षा का अर्थ एवं अवधारणा

बहुविषयक शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शैक्षिक व्यवस्था से है जिसमें विद्यार्थी किसी एक संकीर्ण विषय या अनुशासन तक सीमित न रहकर अनेक विषय क्षेत्रों का अध्ययन करता है। इसमें विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, कला, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, खेल तथा कौशल आधारित विषयों को एक व्यापक शैक्षिक संरचना के अंतर्गत स्थान दिया जाता है।

2.1 बहुविषयकता

Multidisciplinary approach में किसी विषय अथवा समस्या का अध्ययन विभिन्न अनुशासनों के दृष्टिकोण से किया जाता है। प्रत्येक अनुशासन अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखते हुए अध्ययन में योगदान करता है।

उदाहरण के लिए, यदि “जलवायु परिवर्तन” का अध्ययन किया जाए तो इसमें पर्यावरण विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, भूगोल और तकनीकी ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है।

2.2 अंतर्विषयकता

Interdisciplinary education में दो या अधिक विषयों के ज्ञान, सिद्धांतों और विधियों के बीच अधिक गहरा समन्वय स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी समस्या की अधिक समग्र व्याख्या और समाधान प्रस्तुत करना होता है।

2.3 बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा

NEP 2020 केवल विद्यार्थी को अनेक असंबद्ध विषय पढ़ाने की बात नहीं करती, बल्कि बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, नैतिक और व्यावसायिक क्षमताओं के समन्वित विकास की परिकल्पना करती है। UGC भी बहुविषयक संस्थान को केवल अनेक विभाग रखने वाले संस्थान के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे संस्थान के रूप में देखता है जो विभिन्न विषयों को जोड़ने वाले नवाचारी कार्यक्रम विकसित करें।

3. अध्ययन की आवश्यकता

21वीं शताब्दी में शिक्षा, रोजगार और ज्ञान की प्रकृति तेजी से परिवर्तित हो रही है। तकनीक के विस्तार के कारण अनेक पारंपरिक व्यवसायों की प्रकृति बदल रही है तथा नई प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। केवल विषयगत जानकारी की तुलना में सृजनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन, संचार कौशल, समस्या समाधान, डिजिटल साक्षरता और अनुकूलन क्षमता अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है।

भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में लंबे समय तक विज्ञान, कला और वाणिज्य जैसे विषय समूहों के बीच अपेक्षाकृत कठोर विभाजन रहा है। इसके कारण अनेक विद्यार्थी अपनी वास्तविक रुचि के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों के विषयों का संयोजन नहीं कर पाते थे। NEP 2020 इस स्थिति को परिवर्तित करते हुए विद्यार्थी को अधिक विषयगत स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयास करती है।

अतः यह समझना आवश्यक है कि—

1. NEP 2020 में बहुविषयक शिक्षा की वास्तविक अवधारणा क्या है।
2. नीति इसे किस प्रकार लागू करने की परिकल्पना करती है।
3. इससे विद्यार्थियों और उच्च शिक्षण संस्थानों को क्या लाभ हो सकते हैं।
4. इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में कौन-सी समस्याएँ सामने आ सकती हैं।
5. वर्तमान भारतीय शिक्षा व्यवस्था में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किन सुधारों की आवश्यकता है।

4. अध्ययन के उद्देश्य

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वर्णित बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों एवं विशेषताओं का विश्लेषण करना।
3. उच्च शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा से संबंधित NEP 2020 और UGC के प्रमुख प्रावधानों का अध्ययन करना।
4. बहुविषयक शिक्षा से विद्यार्थियों, शिक्षकों और उच्च शिक्षण संस्थानों को होने वाले संभावित लाभों का विश्लेषण करना।
5. बहुविषयक शिक्षा के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना।
6. बहुविषयक शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शैक्षिक सुझाव प्रस्तुत करना।

5. शोध विधि

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, वर्णनात्मक एवं समीक्षात्मक शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन में किसी प्रकार का प्राथमिक सर्वेक्षण, प्रयोग अथवा काल्पनिक सांख्यिकीय डेटा प्रयुक्त नहीं किया गया है। अध्ययन के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से—

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020,
2. उच्च शिक्षा संस्थानों को बहु-विषयक संस्थानों में बदलने के लिए यूजीसी के दिशा-निर्देश,
3. स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम और क्रेडिट फ्रेमवर्क,
4. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट संबंधी प्रावधान,
5. राष्ट्रीय ऋण ढांचा,
6. भारत सरकार एवं UGC के आधिकारिक दस्तावेज,

संकलित साहित्य का विषयगत विश्लेषण करते हुए बहुविषयक शिक्षा की अवधारणा, पाठ्यक्रम लचीलापन, संस्थागत संरचना, कौशल विकास, शैक्षिक गतिशीलता, लाभ तथा क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियों को प्रमुख विश्लेषणात्मक विषयों के रूप में रखा गया है

6. संबंधित साहित्य की समीक्षा

1. **Aithal एवं Aithal (2020)** ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों एवं उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना रखने वाली नीति माना। अध्ययन में बहुविषयकता, संस्थागत पुनर्गठन, विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा तथा लचीली पाठ्यक्रम व्यवस्था को नीति की महत्वपूर्ण विशेषताओं में सम्मिलित किया गया। (IJMTSS)
2. **Yenugu (2022)** ने NEP 2020 के उच्च शिक्षा पर संभावित प्रभाव का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष दिया कि नीति में परिवर्तनकारी क्षमता है, किंतु वास्तविक परिवर्तन के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन, अकादमिक प्रतिबद्धता, संस्थागत क्षमता तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन आवश्यक होगा। (Taylor & Francis Online)
3. **Mitra एवं Sinha (2023)** ने व्यावसायिक एवं विधि शिक्षा के संदर्भ में NEP 2020 की बहुविषयक संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने रेखांकित किया कि नीति सामान्य एवं व्यावसायिक शिक्षा के बीच विद्यमान कठोर विभाजन को कम करती है और विशेषीकृत संस्थानों को भी क्रमशः बहुविषयक स्वरूप की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। (Sage Journals)
4. **Bashir एवं Wani (2024)** ने बहुविषयक तथा समग्र शिक्षा को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से संबंधित बताया। उनके अनुसार विभिन्न विषयों के बीच संबंध स्थापित करने वाली शिक्षा जटिल समस्याओं की समझ, बौद्धिक लचीलापन और व्यापक अधिगम अनुभव को विकसित कर सकती है। (IJIP)
5. **Tamrakar, Tamrakar एवं Thakur (2024)** ने NEP 2020 के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा के नए प्रतिमानों का विश्लेषण किया और पाया कि पाठ्यक्रम की लचीलापन, विविध विषयों के एकीकरण तथा विद्यार्थी-केंद्रित अधिगम के कारण भारतीय उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण परिवर्तन संभव है। साथ ही संस्थागत तैयारी को इसके सफल क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण घटक माना गया। (Granth Aalayah Publication)
6. **Kulal et al. (2024)** ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से NEP 2020 की संभावनाओं और सीमाओं का परीक्षण किया। अध्ययन से यह संकेत मिला कि नीति व्यापक परिवर्तन की क्षमता रखती है, लेकिन व्यावहारिक कार्यान्वयन की गुणवत्ता विभिन्न हितधारकों के अनुभवों और संस्थागत परिस्थितियों पर निर्भर करती है। (Sage Journals)

7. **Kumar, Ashok et al. (2025)** की व्यापक समीक्षा में पाया गया कि NEP 2020 competency-based learning, experiential learning, equity, innovation और आधुनिक शैक्षिक आवश्यकताओं को महत्व देती है। साथ ही संसाधनों की कमी, प्रशासनिक कठिनाइयों और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध को प्रमुख क्रियान्वयन चुनौतियों के रूप में पहचाना गया। (PubMed)

8. **Kumar एवं Jain (2026)** ने उच्च शिक्षण संस्थानों में NEP 2020 के कार्यान्वयन की चुनौतियों का गुणात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी, बहुविषयक, कौशल-आधारित और शोधोन्मुख बनाने की नीति की क्षमता स्वीकार की गई, परंतु इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन में अनेक संस्थागत समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। (Granth Aalayah Publication)

उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश विद्वान बहुविषयक शिक्षा को NEP 2020 की परिवर्तनकारी विशेषता मानते हैं, लेकिन नीति की सफलता का वास्तविक निर्धारण उसके प्रभावी, संसाधन-संपन्न और संस्थागत रूप से समन्वित क्रियान्वयन से होगा।

7. NEP 2020 में बहुविषयक शिक्षा के प्रमुख प्रावधान

7.1 विषयों के बीच कठोर विभाजन का अंत

NEP 2020 का एक केंद्रीय सिद्धांत कला, मानविकी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यावसायिक विषयों के बीच कठोर सीमाओं को कम करना है। इससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकता है।

उदाहरणस्वरूप विज्ञान का विद्यार्थी संगीत, अर्थशास्त्र अथवा दर्शन का अध्ययन कर सकता है, जबकि मानविकी का विद्यार्थी डेटा विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान या तकनीकी कौशल से जुड़े विषय चुन सकता है।

7.2 Major और Minor की व्यवस्था

बहुविषयक पाठ्यक्रम विद्यार्थी को एक मुख्य विषय अर्थात् Major के साथ दूसरे विषय को Minor के रूप में चुनने का अवसर देता है। इससे विशेषज्ञता और व्यापक ज्ञान दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है।

UGC का Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes विद्यार्थी-केंद्रित लचीले credit system, multidisciplinary approach तथा multiple entry-exit विकल्पों को बढ़ावा देता है। (UGC)

7.3 तीन अथवा चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम

NEP 2020 के अनुसार स्नातक कार्यक्रम तीन या चार वर्ष की अवधि के हो सकते हैं। चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम को समग्र और बहुविषयक अध्ययन की अधिक व्यापक संभावनाओं के कारण विशेष महत्व दिया गया है। (Education)

7.4 Multiple Entry और Multiple Exit

विद्यार्थियों के लिए अध्ययन को अधिक लचीला बनाने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य उन विद्यार्थियों को भी शैक्षणिक मान्यता देना है जो किसी कारण से निर्धारित अवधि में पूरा कार्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाते।

7.5 Academic Bank of Credits

Academic Bank of Credits विद्यार्थियों द्वारा अर्जित academic credits के डिजिटल संचयन, हस्तांतरण और उपयोग को सुविधाजनक बनाने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य विभिन्न मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच विद्यार्थी की शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ाना है। UGC के अनुसार ABC credit recognition, accumulation, transfer और redemption की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। (UGC)

7.6 राष्ट्रीय ऋण ढांचा

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं अनुभवात्मक अधिगम को एक व्यापक credit व्यवस्था में समाहित करने का प्रयास करता है। इसके अपेक्षित परिणामों में बहुविषयक एवं समग्र शिक्षा, लचीला पाठ्यक्रम, lifelong learning तथा academic और vocational streams के बीच कठोर विभाजन को कम करना सम्मिलित है। (UGC)

7.7 बहुविषयक विश्वविद्यालय

NEP 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा में fragmentation को कम करना है। UGC के दिशा-निर्देशों में भविष्य की उच्च शिक्षा संरचना में—

- बहु-विषयक अनुसंधान-गहन विश्वविद्यालय,
- बहु-विषयक शिक्षण-गहन विश्वविद्यालय तथा
- डिग्री प्रदान करने वाले बहु-विषयक स्वायत्त कॉलेज

जैसी संस्थागत संरचनाओं की परिकल्पना की गई है। (UGC)

7.8 व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा का एकीकरण

बहुविषयक शिक्षा में कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा को सामान्य शिक्षा से अलग नहीं माना जाता। इंटरनशिप, स्थानीय उद्योग, उद्यमिता, कलाकारों, कारीगरों और शोध संस्थानों से जुड़ाव के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव देने पर बल दिया गया है। (UGC)

7.9 शोध एवं नवाचार

बहुविषयक शिक्षा शोध को विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों से जोड़ने की क्षमता प्रदान करती है। आधुनिक समस्याएँ अक्सर अनेक विषयों से संबंधित होती हैं। अतः पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक और समाज जैसे क्षेत्रों में बहु-विषयक अनुसंधान की आवश्यकता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

8. बहुविषयक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएँ

बहुविषयक शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है—

1. विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा।
2. विषय चयन में स्वतंत्रता।
3. कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक शिक्षा का समन्वय।
4. Major एवं Minor विषयों की व्यवस्था।
5. लचीली पाठ्यक्रम संरचना।
6. कौशल तथा व्यावसायिक शिक्षा का समावेश।
7. सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान का संतुलन।
8. शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहन।
9. आलोचनात्मक तथा सृजनात्मक चिंतन का विकास।
10. स्थानीय और वैश्विक ज्ञान का समन्वय।
11. मूल्य एवं नैतिक शिक्षा का समावेश।
12. इंटरनशिप तथा अनुभवात्मक शिक्षा पर बल।
13. शैक्षणिक गतिशीलता की सुविधा।
14. आजीवन अधिगम की संभावना।
15. रोजगारपरक एवं transferable skills का विकास।

9. बहुविषयक शिक्षा का महत्व

9.1 समग्र व्यक्तित्व विकास

बहुविषयक शिक्षा विद्यार्थियों के केवल बौद्धिक पक्ष पर ध्यान नहीं देती बल्कि उसके सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, शारीरिक और सृजनात्मक विकास को भी महत्व देती है।

9.2 आलोचनात्मक चिंतन

विभिन्न विषयों का अध्ययन विद्यार्थी को एक ही समस्या को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इससे वह सूचनाओं को केवल स्वीकार करने के बजाय उनका विश्लेषण एवं मूल्यांकन करना सीखता है।

9.3 समस्या समाधान क्षमता

वर्तमान समाज की अधिकांश समस्याएँ एकविषयक नहीं हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की समस्या को समझने के लिए चिकित्सा विज्ञान के साथ समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और प्रशासन की समझ भी उपयोगी है।

9.4 सृजनात्मकता और नवाचार

भिन्न ज्ञान क्षेत्रों का संपर्क नवीन विचार उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है। विज्ञान और डिजाइन, तकनीकी ज्ञान और मनोविज्ञान अथवा शिक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे संयोजन नए शोध एवं नवाचार को जन्म दे सकते हैं।

9.5 रोजगारपरकता

आधुनिक रोजगार क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों की मांग करता है जिनके पास विषयगत ज्ञान के साथ communication, problem-solving, digital skills, teamwork तथा adaptability जैसी क्षमताएँ हों। बहुविषयक पाठ्यक्रम इन क्षमताओं के विकास की संभावना बढ़ाता है।

9.6 विद्यार्थी की रुचि को महत्व

यह व्यवस्था विद्यार्थी को केवल परंपरागत धारा के आधार पर विषय चुनने के लिए बाध्य करने की बजाय उसकी व्यक्तिगत रुचियों और भविष्य के लक्ष्यों को महत्व देती है।

9.7 शोध की गुणवत्ता

जब शोधकर्ता विभिन्न ज्ञान क्षेत्रों की विधियों एवं दृष्टिकोणों का उपयोग करता है, तो जटिल समस्याओं पर अधिक व्यापक और नवीन शोध संभव हो सकता है।

10. बहुविषयक शिक्षा के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौतियाँ

बहुविषयक शिक्षा का दृष्टिकोण आकर्षक होने के बावजूद इसके सफल क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ हैं।

10.1 योग्य शिक्षकों की कमी

छोटे महाविद्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के संस्थानों में विभिन्न विषयों के पर्याप्त शिक्षकों की उपलब्धता सीमित हो सकती है। अनेक विकल्प प्रदान करने के लिए विविध विशेषज्ञता वाले संकाय सदस्यों की आवश्यकता होगी।

10.2 अवसंरचना की समस्या

प्रयोगशाला, पुस्तकालय, ICT संसाधन, डिजिटल नेटवर्क, कला एवं खेल सुविधाएँ तथा vocational laboratories बहुविषयक कार्यक्रमों के लिए आवश्यक हैं। सभी संस्थानों की आर्थिक एवं भौतिक क्षमता समान नहीं है।

10.3 पाठ्यक्रम निर्माण

केवल अलग-अलग विषय जोड़ देना वास्तविक बहुविषयक शिक्षा नहीं है। पाठ्यक्रमों के बीच तार्किक संबंध स्थापित करना तथा duplication से बचना विशेषज्ञ पाठ्यक्रम नियोजन की मांग करता है।

10.4 शिक्षक प्रशिक्षण

बहुविषयक शिक्षा में शिक्षक को पारंपरिक व्याख्यान-आधारित शिक्षण से आगे बढ़कर collaborative learning, project work, experiential learning तथा अंतःविषय शिक्षाशास्त्र का उपयोग करना होगा। इसके लिए नियमित संकाय विकास कार्यक्रम आवश्यक हैं। UGC के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट संबंधी प्रावधान भी holistic/multidisciplinary education के समर्थन में संकाय विकास और व्यावसायिक विकास की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। (UGC)

10.5 संस्थागत समन्वय

अलग-अलग विभागों में timetable, credits, assessment और शैक्षणिक नियम का समन्वय करना प्रशासनिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

10.6 संसाधनों की असमानता

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अनेक विषयों और आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था अपेक्षाकृत आसानी से कर सकते हैं, जबकि ग्रामीण या कम संसाधन वाले महाविद्यालय समान अवसर उपलब्ध कराने में कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। इससे शैक्षिक असमानता बढ़ने का जोखिम रहता है।

10.7 विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन

अत्यधिक विषय विकल्प विद्यार्थियों के लिए भ्रम भी उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए प्रभावी शैक्षणिक परामर्श तथा कैरियर मार्गदर्शन आवश्यक है।

10.8 गुणवत्ता सुनिश्चित करना

विषय चयन में लचीलेपन के साथ यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विद्यार्थी अपने मुख्य विषय में आवश्यक गहराई एवं विशेषज्ञता भी प्राप्त करे। “विस्तार” और “विशेषज्ञता” के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

10.9 प्रशासनिक मानसिकता में परिवर्तन

बहुविषयक शिक्षा केवल पाठ्यचर्या सुधार नहीं है; इसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रशासनिक एवं अकादमिक संस्कृति में भी परिवर्तन आवश्यक है।

11. अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

1. बहुविषयक शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की केंद्रीय अवधारणाओं में से एक है।
2. इसका उद्देश्य विभिन्न विषयों का केवल यांत्रिक संयोजन नहीं, बल्कि विद्यार्थी के समग्र विकास के लिए ज्ञान क्षेत्रों के बीच सार्थक संबंध स्थापित करना है।
3. NEP 2020 कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा के बीच कठोर सीमाओं को कम करती है।
4. पाठ्यचर्या और क्रेडिट ढांचा, मेजर-माइनर व्यवस्था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क बहुविषयक शिक्षा को व्यावहारिक रूप देने वाले महत्वपूर्ण तंत्र हैं।
5. बहुविषयक शिक्षा से विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता, नवाचार तथा रोजगारपरक कौशल के विकास की संभावना बढ़ती है।
6. यह व्यवस्था विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं करियर उद्देश्य के अनुरूप विभिन्न विषय चुनने की अधिक स्वतंत्रता प्रदान करती है।
7. बहुविषयक शोध सामाजिक, तकनीकी, पर्यावरणीय और शैक्षिक समस्याओं के अधिक व्यापक समाधान में सहायक हो सकता है।
8. नीति की सफलता केवल दस्तावेजी प्रावधानों पर नहीं बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों की वास्तविक क्षमता पर निर्भर करेगी।
9. वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रम समन्वय और शैक्षणिक परामर्श इसके प्रमुख क्रियान्वयन क्षेत्र हैं।

10. ग्रामीण और संसाधन-वंचित संस्थानों को विशेष सहायता दिए बिना बहुविषयक शिक्षा के अवसरों में संस्थागत असमानता उत्पन्न हो सकती है।
11. उच्च शिक्षा में बहुविषयकता के सफल कार्यान्वयन के लिए विभागीय सीमाओं से आगे सहयोगात्मक शैक्षणिक संस्कृति विकसित करना आवश्यक है।
12. बहुविषयक शिक्षा भारत की उच्च शिक्षा को अधिक लचीला, विद्यार्थी-केंद्रित, कौशलोन्मुख तथा भविष्य की सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की क्षमता रखती है।

12. शैक्षिक निहितार्थ

1. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अंतर्विषयक तथा बहु-विषयक पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
2. विद्यार्थियों के लिए मजबूत शैक्षणिक परामर्श प्रणाली स्थापित होना चाहिए।
3. शिक्षकों को बहु-विषयक शिक्षाशास्त्र में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
4. परियोजना आधारित एवं अनुभवात्मक शिक्षा को पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक बनाया जाना चाहिए।
5. कला, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक विभागों के बीच संयुक्त कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।
6. ग्रामीण एवं कम संसाधन वाले संस्थानों को अतिरिक्त वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
7. एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट ट्रांसफर व्यवस्था के संबंध में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
8. स्थानीय उद्योग, समुदाय और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए।
9. बहुविषयक शोध परियोजनाओं के लिए विभिन्न विभागों के शिक्षकों एवं शोधार्थियों को संयुक्त रूप से कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए।
10. पाठ्यक्रम की लचीलापन और विषयगत विशेषज्ञता के बीच उचित संतुलन बनाए रखा जाना चाहिए।

13. सुझाव

1. उच्च शिक्षण संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से बहुविषयक कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
2. शिक्षकों के लिए नियमित FDP, Orientation और अंतःविषय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।

3. विभिन्न विभागों के संयुक्त शिक्षण एवं संयुक्त शोध को प्रोत्साहन दिया जाए।
4. विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक संस्थान में अकादमिक सलाहकार की व्यवस्था की जाए।
5. डिजिटल एवं भौतिक अवसंरचना को मजबूत किया जाए।
6. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित किए जाएँ।
7. क्रेडिट हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए।
8. पाठ्यक्रम निर्माण में विश्वविद्यालय, शिक्षक, उद्योग, विद्यार्थी और विषय विशेषज्ञों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
9. ग्रामीण महाविद्यालयों के लिए क्लस्टर-आधारित बहु-विषयक मॉडल विकसित किया जा सकता है।
10. बहुविषयक शिक्षा के परिणामों का समय-समय पर मूल्यांकन किया जाए।
11. केवल अधिक विषय उपलब्ध कराने के बजाय वास्तविक ज्ञान-समन्वय पर बल दिया जाए।
12. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शोध, कौशल और रोजगारपरकता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।

14. निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। यह परंपरागत विषयगत सीमाओं को कम करते हुए विद्यार्थी को ज्ञान के विविध क्षेत्रों से जुड़ने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करने योग्य स्नातक तैयार करना नहीं, बल्कि सृजनात्मक, आलोचनात्मक, नैतिक, सामाजिक रूप से उत्तरदायी एवं समस्याओं के समाधान में सक्षम व्यक्तियों का निर्माण करना है।

NEP 2020 में प्रस्तावित बहुविषयक विश्वविद्यालय, लचीली पाठ्यक्रम संरचना, Major-Minor प्रणाली, multiple entry-exit, Academic Bank of Credits, vocational integration और National Credit Framework इस अवधारणा को व्यावहारिक आधार प्रदान करते हैं। UGC की वर्तमान उच्च शिक्षा पहलें भी लचीली विकल्प-आधारित क्रेडिट प्रणाली और बहु-विषयक शिक्षा को आगे बढ़ाती हैं। (UGC) तथापि, बहुविषयक शिक्षा की सफलता केवल नीति निर्माण से संभव नहीं होगी। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक, आधुनिक आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रम में वास्तविक विषयगत समन्वय, संस्थागत स्वायत्तता, प्रशासनिक सहयोग तथा विद्यार्थियों के लिए प्रभावी अकादमिक मार्गदर्शन समान रूप से आवश्यक हैं। हाल के अध्ययनों में भी संसाधन, प्रशासनिक तैयारी एवं कार्यान्वयन क्षमता को NEP 2020 के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया है। (PubMed)

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि यदि बहुविषयक शिक्षा को केवल औपचारिक पाठ्यक्रम परिवर्तन के रूप में न लेकर व्यापक शैक्षिक दर्शन के रूप में लागू किया जाए, तो यह भारतीय उच्च

शिक्षा को अधिक लचीला, समावेशी, नवाचारोन्मुख, शोधपरक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ

1. Aithal, P. S., & Aithal, S. (2020). Analysis of the Indian National Education Policy 2020 towards achieving its objectives. *International Journal of Management, Technology, and Social Sciences*, 5(2), 19–41. doi:10.47992/IJMTS.2581.6012.0102.
2. Ashokkumar, T., Raj, T. R., Rajadurai, A., Abishini, A. H., & Anchani, A. H. (2025). Analyzing the impact of the new educational policy 2020: A comprehensive review of India's educational reforms. *Evaluation and Program Planning*, 108, 102515. doi:10.1016/j.evalprogplan.2024.102515.
3. Bashir, L., & Wani, G. (2024). Multidisciplinary and holistic education: Achieving academic excellence and bolstering all-round development in the 21st century with NEP-2020. *International Journal of Indian Psychology*, 12(1).
4. Government of India, Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. New Delhi: Government of India.
5. Kandwal, N. P., & Negi, S. (2025). National Education Policy 2020: Paving the path for holistic management education in India. *International Journal of Engineering and Management Research*, 14(6), 38–45. doi:10.31033/IJEMR.14.6.38-45.
6. Kulal, A., Abhishek, N., Dinesh, S., Bhat, D. C., & Girish, A. (2024). Evaluating the promise and pitfalls of India's National Education Policy 2020: Insights from the perspectives of students, teachers, and experts. *SAGE Open*. doi:10.1177/21582440241279367.
7. Kumar, M., & Jain, V. K. (2026). Challenges in the implementation of National Education Policy 2020 in higher educational institutions: A qualitative study. *International Journal of Research – GRANTHAALAYAH*, 14(5). doi:10.29121/granthaalayah.v14.i5.2026.6946.
8. Mandal, C. (2024). Multidisciplinary approaches in NEP 2020: Opportunities and challenges in India. *Archives*.
9. Mehta, S. (2025). Reinventing inclusive and holistic education: Indigenous knowledge systems and the National Education Policy (2020). doi:10.1177/0972558X251361776.

10. Mitra, N. L., & Sinha, M. K. (2023). National Education Policy 2020 and challenges to the Bar Council of India. *Journal of National Law University Delhi*, 10(1). doi:10.1177/23220058221138121.
11. Tamrakar, L., Tamrakar, S., & Thakur, V. (2024). Multidisciplinary education: New paradigms under NEP 2020. *ShodhKosh: Journal of Visual and Performing Arts*, 5(2), 496–500. doi:10.29121/shodhkosh.v5.i2.2024.2221.
12. University Grants Commission. (2021). *University Grants Commission (Establishment and Operation of Academic Bank of Credits in Higher Education) Regulations, 2021*. New Delhi: UGC.
13. University Grants Commission. (2022). *Guidelines for Transforming Higher Education Institutions into Multidisciplinary Institutions*. New Delhi: UGC.
14. University Grants Commission. (2022). *Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes*. New Delhi: UGC.
15. University Grants Commission. (2023). *National Credit Framework*. New Delhi: University Grants Commission.
16. University Grants Commission. (2023). *Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes: Key Initiatives*. New Delhi: UGC.
17. University Grants Commission. (2026). *Academic Bank of Credits: Key Initiatives*. New Delhi: UGC.
18. Verma, S., Shrivastava, P., & Singh, A. (2025). Multidisciplinary learning and flexibility in NEP 2020: A new era of Indian education. *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies*, 11(5), 119–129.
19. Yenugu, S. (2022). The new National Education Policy (NEP) of India: Will it be a paradigm shift in Indian higher education? *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 26(4), 121–129. doi:10.1080/13603108.2022.2078901.